जब सबूत अभी तक पूरा नहीं हुआ था क्योंकि गवाहों से जिरह नहीं की गई थी, तो आवेदन की अनुमति दी और आरोपी को तलब किया। इन तथ्यों पर गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने तलब आदेश को रद्द कर दिया था। लेकिन, उचित सम्मान के साथ, मैं उसी दृष्टिकोण से सहमत नहीं *हो पा रहा* हूं। हाल *ही में, राज* किशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य (11) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:—

> "आरोपमुक्त अभियुक्त को बुलाकर या फिर से बुलाकर अभियुक्त को जोड़ने की अनुमति, और वह भी अभियुक्त को सुने बिना, केवल धारा 319 दंड संहिता द्वारा प्रदान किए गए तरीके से दी गई है। मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य पर, और किसी अन्य तरीके से नहीं।"

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को संहिता की धारा 319 के तहत निचली अदालत द्वारा तलब किए जाने तक उन्हें गवाह बाल कृष्ण से जिरह करने का कोई अधिकार नहीं था।

(27) इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह अब सुसंगत *नहीं* है कि ऐसा अभियुक्त जिसके खिलाफ संहिता की धारा 319 के तहत आदेश पारित किया गया है, उसे उस आदेश को पारित करने से पहले सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।

(28) तदनुसार, याचिका में कोई योग्यता नहीं पाए जाने पर इसे खारिज कर दिया जाता है।

(29) आदेश की प्रति विचारण न्यायाधीश को प्रेषित की जाए ताकि वह त्रयी के साथ आगे बढ़ सके।

एस. सी. के.

मुख्य न्यायमूर्ति अरुण बी. सहारिया, और न्यायमूर्ति एच. एस. बेदी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य,-अपीलार्थी

बनाम

डी. सी. *अग्रवाल,-उत्तरदाता*

***1998* का एल. पी. ए. सं. 364**

9 मार्च, 1999

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-*पेटेंट अपील पत्र, 1919-सी. एल. एक्स-बैंक की 8 जून, 1982 की पदोन्नति नीति, जिसे 23 फरवरी, 1984 की नीति द्वारा अधिसूचित किया गया है -माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत पदोन्नति के दावे पर पुनर्विचार-शीर्ष कार्यकारी ग्रेड स्केल VII (महाप्रबंधक) में पदोन्नति के लिए अपनी उपयुक्तता का फैसला करने के लिए साक्षात्कार के बाद उत्तरदाता के दावे को नकार दिया गया-अधिकारी ने साक्षात्कार में केवल 25.7% अंक प्राप्त किए जो निर्धारित 60 प्रतिशत योग्यता अंकों से बहुत कम थे-उत्तरदाता ने केवल न्यायशास्त्र को चुनौती दी-साक्षात्कार लेने के लिए समिति का गठन।— न्यायालय का निर्णय लेने वाले उत्तरदाता का कभी भी इसे साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत करने का इरादा नहीं था, बल्कि केवल विलंभ करने और इसे रद्द करने के लिए-अधिकारी को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संक्षिप्त किए गए साक्षात्कार पर हमला करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-विद्वान एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष कि 1 अगस्त, 1984 और 1 अगस्त, 1988 के बीच पदोन्नति मामले की टी. ई. जी. स्केल VII में जांच करने की आवश्यकता है-विद्वान एकल न्यायाधीश 1989 की नीति के आधार पर मामले का निर्णय लेते हुए कि*

इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है-1984 विद्वान एकल न्यायाधीश के नोटिस से बचने की नीति-इसलिए, निष्कर्ष को रद्द कर दिया गया -नवंबर, 92 से जून, 93 तक वेतन के लिए उत्तरदाता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह हैदराबाद में स्थानांतरण पर कर्तव्य में शामिल नहीं हुआ था-उत्तरदाता के अपने मामले में सर्वोच्च न्यायालय-यह कि उत्तरदाता की हैदराबाद में नियुक्ति उचित नहीं थी और उसे फिर से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया है-वेतन के भुगतान के उत्तरदाता के दावे के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्देश पूरी तरह से उचित था।

अभिनिर्धारित किया कि उत्तरदाता का कभी भी साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत होने का इरादा नहीं था, बल्कि विलंभ करने और अंततः इसे रद्द करने का इरादा था। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तरदाता को स्वभाव से ''उत्तेजक'' पाया था, एक ऐसी टिप्पणी जिसके साथ हम दिल से सहमत हैं, लेकिन इसके अलावा, कई दिनों तक उसे सुनने के बाद, हम उसे एक बेहद मुखर और बुद्धिमान व्यक्ति भी पाते हैं। इसलिए, हम आश्वस्त हैं कि उत्तरदाता अपने कार्यों के परिणामों के बारे में पूरी तरह से अवगत था। इसलिए, साक्षात्कार समिति को उनकी हठधर्मिता के कारण साक्षात्कार में कटौती करने के लिए पूरी तरह से उचित ठहराया गया था।

(पैरा 11)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह सच है जैसा कि उत्तरदाता द्वारा तर्क दिया गया है कि उत्तरदाता से पूछे गए प्रश्न सभी 14 निर्धारित मापदंडों के पर्याप्त रूप से अनुरूप नहीं थे, लेकिन हमारी राय है कि पहले से ही दर्ज किए गए कारणों से कि उत्तरदाता स्वयं इस स्थिति के लिए जिम्मेदार था।

(पैरा 11)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि उत्तरदाता ने साक्षात्कार के समय तुच्छ आपत्तियां उठाई थीं और जाहिर तौर पर वह साक्षात्कार के समय मनोदशा मे नहीं था और इस स्थिति में अब वह शिकायत नहीं कर सकता कि साक्षात्कार समिति ने उसका उचित मूल्यांकन नहीं किया था। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि समिति भारतीय स्टेट बैंक के तीन उप महाप्रबंधकों की थी और उनमें से किसी के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। हमने 14 संकेतकों के संबंध में किए गए वास्तविक मूल्यांकन को भी देखा है और पाया है कि प्रत्येक व्यक्तिगत पैरामीटर के लिए अंक दिए गए हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि मूल्यांकन 8 जून, 1982 की नीति में उल्लिखित विभिन्न संकेतों के अनुसार नहीं किया गया था, इसलिए सही नहीं है।

(पैरा 11)

13 अक्टूबर, 1992 (भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम डी. सी. अग्रवाल और अन्य, 1993 (1) एस. सी. सी. 13) में सिविल अपील संख्या 4213 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ने से हमें पता चलता है कि हालांकि बैंक द्वारा विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जांच के दौरान उत्तरदाता को केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट की आपूर्ति न करने के परिणामों के संबंध में केवल सीमित मुद्दे पर अपना निर्णय दिया था। इसलिए, उत्तरदाता के लिए यह आग्रह करने के लिए खुला नहीं है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए पूर्वाग्रह के निष्कर्ष का माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समर्थन किया गया था। हम मानवीय कमजोरियों से अनजान नहीं हो सकते हैं, और बैंक में अपने वरिष्ठों के प्रति उत्तरदाता का अपमानजनक व्यवहार, विशेष रूप से उन लोगों के प्रति जो वह शत्रुतापूर्ण मानते थे और अन्य जो किसी स्तर पर उनके कनिष्ठ हो सकते थे, उनके प्रति उनके रवैये को प्रभावित कर सकते थे और यह निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य

से था जिसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें उत्तरदाता के पक्ष में आदेश देने के लिए प्रेरित किया था और साथ ही संबंधित अपील भी। हमारी यह राय है कि चूंकि उत्तरदाता की पदोन्नति के मामले पर बैंक के कुछ वरिष्ठ सदस्यों द्वारा विचार किया गया था और चूंकि उनमें से किसी को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए संस्थागत पूर्वाग्रह का व्यापक आरोप स्वीकार्य नहीं है।

(पैरा 12)

भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षी कर्मचारी) सेवा नियम, 1975-नियम 20-भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी सेवा नियम, 1992-नियम 19-58 वर्ष से अधिक *की सेवा में विस्तार-समीक्षा समिति-एकल न्यायाधीश ने समीक्षा समिति की सिफारिश को इस कारण से मनमाना घोषित किया कि नियंत्रक प्राधिकरण ने सिफारिशों को आगे बढ़ाते समय उत्तरदाता के रिकॉर्ड की गलत तस्वीर पेश की-उत्तरदाता ने दो सदस्य समीक्षा समिति और सक्षम प्राधिकारी के संविधान पर कोई आपत्ति नहीं की-विस्तार से इनकार करने में दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया-सेवा में विस्तार देने का विवेक सक्षम प्राधिकारी में निहित है-कोई सबूत नहीं है कि विवेक का अनुचित उपयोग किया गया-हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया-अपील खारिज कर दी गई और एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया गया।*

अभिनिर्धारित किया गया कि उत्तरदाता ने इस स्थिति को इस कारण से स्वीकार किया है कि उसने अपने अभिवचनों के दौरान और यहां तक कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष भी दो सदस्यीय समीक्षा समिति और सक्षम प्राधिकारी के गठन पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी और यह इस अपील में हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्नों के कारण था जिसने उसे पहली बार इस याचिका को लेने के लिए प्रेरित किया।

(पैरा 26)

वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के साथ संजय कपूर, अशोक गुप्ता और ओ. पी. सदाना, अपीलार्थियों *के अधिवक्ता*

डी. सी. *अग्रवाल, प्रतिवादी, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित*

निर्णय

हरजीत सिंह बेदी, न्यायमूर्ति

(1) ये अपीलें निम्नलिखित तथ्यों से उत्पन्न होती हैं:

(2) श्री डी. सी. अग्रवाल, इसमें उत्तरदाता, 15 जनवरी, 1960 को अपीलकर्ता-भारतीय स्टेट बैंक की सेवा में शामिल हुए और समय-समय पर विभिन्न पदोन्नति प्राप्त करने के बाद 27 जुलाई, 1980 से शीर्ष कार्यकारी ग्रेड स्केल VI (टी. ई. जी.) में पदोन्नत हुए और इस पदोन्नति के आधार पर उप महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रभारी के रूप में चंडीगढ़ में मुख्यालय के साथ तैनात किए गए। हालाँकि, उन्हें 1 जुलाई, 1981 को उस अवधि से संबंधित कदाचार के लिए विभागीय जांच के विचार में निलंबित कर दिया गया था जब उन्हें बैंक ऑफ धनबाद के शाखा प्रबंधक के रूप में तैनात किया गया था। तमिलनाडु कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी श्री आर. के. रस्तोगी को तदनुसार जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने 30 मई, 1985 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उत्तरदाता को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी करते हुए कहा गया कि वे केवल मनगढ़ंत थे और उत्तरदाता के आचरण को बदनाम करने का प्रयास था और उस उद्देश्य के लिए जांच अधिकारियों ने उसे फंसाने के लिए सबूत बनाने की कोशिश की थी। तथापि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों से असहमत थे और जांच अधिकारी ने उत्तरदाता पर दो

चरणों में रैंक में कमी का जुर्माना लगाया, जिसके बाद उत्तरदाता को मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल-IV में वापस कर दिया गया। इस कार्रवाई को उत्तरदात द्वारा 1989 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 15874 में चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने 9 अप्रैल, 1991 *के एक फैसले में (और डी. सी. अग्रवाल बनाम* भारतीय स्टेट बैंक और अन्य[1] के रूप में सूचित किया गया था), रिट याचिका को यह मानते हुए अनुमति दी कि उत्तरदाता पर लगाया गया दंड बहुत कठोर था और फाइल पर तथ्यों द्वारा वारंट नहीं था। तदनुसार विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया और उसके पक्ष में कुछ परिणामी लाभों का आदेश दिया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर, बैंक ने 1991 की लेटर पेटेंट अपील संख्या 553 दायर की, जिसे 15 मई, 1991 को एक खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था। 1991 की एक विशेष अनुमति याचिका संख्या 10198 भी दायर *की गई थी और अनुमति दी गई थी, लेकिन पक्षों को सुनने के बाद अपील* को 13 अक्टूबर, 1992 को भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम डी. सी. अग्रवाल और अन्य[2] के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि सक्षम प्राधिकारी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा किया था और चूंकि इसकी एक प्रति उत्तरदाता को प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए वह अपने बचाव में पूर्वाग्रह से ग्रस्त था और इस प्रकार, उसे पद से कम करने के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता था। इसके बाद उत्तरदाता को एक नई विभागीय जांच शुरू *करने* के लिए 28 दिसंबर, 1992 को एक नोटिस दिया गया था। उत्तरदाता ने सर्वश्री वी. एम. अहादेवन और पी. वी. सुब्बा राव, अपीलार्थी-बैंक और नियम निसी के दो प्रबंध निदेशकों के खिलाफ 1992 का 1098 दायर किया। इस आदेश को अवमानकर्ताओं द्वारा 1993 के एस. एल. पी. सं. 1707-08 में चुनौती दी गई थी और अनुमति दिए जाने पर, 1993 की सिविल अपील सं. 4017-18 का निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटारा किया गया थाः—

> "(i) विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का बयान स्वीकार किया जाता है कि उत्तरदाता के खिलाफ उस अधिनियम या आयोग के लिए कोई नई जांच नहीं की जाएगी जिसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 1987 में रैंक से कमी आई थी। 28 दिसंबर, 1992 का नोटिस वापस ले लिया जाएगा।
>
> (ii) भारतीय स्टेट बैंक उत्तरदाता की पदोन्नति के दावे पर नियमों के अनुसार उच्च स्तर पर पुनर्विचार करेगा। हम इस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं कि क्या उच्च स्तर के लिए एक साक्षात्कार आवश्यक है और क्या प्रतिवादी को बढ़ावा नहीं देने के लिए कोई वैध औचित्य था। *जिनका इन कार्यवाहियों से पहले का रिकॉर्ड बेदाग है, लेकिन यदि बैंक द्वारा बनाई गई नीति के तहत और अन्य मामलों में एक समिति का गठन और साक्षात्कार आवश्यक है तो समिति का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय कार्यालय, बॉम्बे और प्रबंध निदेशक (कार्मिक), भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय कार्यालय, बॉम्बे, जो इस न्यायालय में अपीलकर्ता हैं, इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं।*
>
> (iii) समिति का गठन आज से तीन सप्ताह के भीतर किया जाएगा जो यह तय करेगी कि क्या उत्तरदाता उच्च स्तर पर पदोन्नत होने का हकदार था जिसमें उसके कनिष्ठ काम कर रहे हैं क्योंकि हमें सूचित किया जाता है कि उत्तरदाता अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँच रहा है। यदि समिति उत्तरदाता

[1] 1991(2) S.L.R. 578.
[2] J.T. 1992 (6) S.C. 673

को पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाती है तो वह इसके लिए कारण बताएगी।

(iv) इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही रद्द कर दी जाएगी।''

(3) शुरुआत में दिए गए निर्देशों के साथ, चंडीगढ़ में बैंक के स्थानीय मुख्य कार्यालय में स्थित जनरल एमए (संचालन) ने 26 अगस्त, 1993 को पत्र अनुलग्नक पी-7 जारी किया, जिसमें उत्तरदाता से एक साक्षात्कार में भाग लेने का आह्वान किया गया ताकि टीईजी स्केल VII (महाप्रबंधक) पद पर पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता का निर्णय लिया जा सके। उत्तरदाता 1 सितंबर, 1993 को साक्षात्कार समिति के समक्ष पेश हुआ और मूल्यांकन पर केवल 25.7% अंक दिए गए, जिस पर पदोन्नति के लिए उसके दावे को 8 सितंबर, 1993 के अनुलग्नक पी-8 के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। उत्तरदाता ने इस आदेश के खिलाफ 15 सितंबर, 1993 के अनुलग्नक पी-9 के माध्यम से अपीलार्थी-बैंक के अध्यक्ष को साक्षात्कार समिति की कार्यवाही का विरोध करते हुए एक अभ्यावेदन दिया। उन्होंने बैंक के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए C.R. No. 324—93 in C.A. No. 4017-18/1993 दाखिल करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन 17 सितंबर, 1993 को आदेश अनुलग्नक पी-8 के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस ले लिया। 1993 की सिविल रिट याचिका संख्या 15245 तदनुसार उत्तरदाता-लिखित याचिकाकर्ता द्वारा 18 सितंबर, 1993 के अनुलग्नक पी-8 और 27 मई, 1993 के अनुलग्नक पी-5 द्वारा दायर की गई थी, जिसमें नवंबर 1992 से 16 जून, 1993 की अवधि के लिए वेतन के भुगतान के उनके दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि हालांकि उन्हें हैदराबाद में तैनात किया गया था, वे उस स्थान पर शामिल नहीं हुए थे और बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहे थे। रिट याचिका में विद्वत एकल न्यायाधीश ने पक्षों के बीच के मुद्दों को नोट किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चूंकि उत्तरदाता-लिखित याचिकाकर्ता के मामले पर पहली बार 1 अगस्त, 1984 से 1 अगस्त, 1988 के बीच चार अलग-अलग तिथियों पर विचार किया जाना था, इसलिए यह मूल्यांकन 8 जून, 1982 के बैंक अनुलग्नक पी-1 की पदोन्नति नीति के तहत किया जाना था, जिसमें प्रबंध निदेशक और कुछ अन्य अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत का प्रावधान था, लेकिन एक विभागीय पदोन्नति समिति के रूप में, 1 सितंबर, 1993 को, पदोन्नति नीति, अनुलग्नक पी-2, दिनांक 1 मार्च, 1989 के अनुसार उत्तरदाता की योग्यता का मूल्यांकन किया गया था, जो बाद में समय के बिंदु पर था और इसके लिए प्रावधान किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि 8 जून, 1982 की नीति अनुलग्नक पी-1 में उल्लिखित विभिन्न संकेतों के आलोक में उत्तरदाता की योग्यता का आकलन करने में मध्यस्थ समिति की विफलता इस निष्कर्ष का समर्थन करती है कि उत्तरदाता के साथ मनमाने और अनुचित तरीके से व्यवहार किया गया था। विद्वत एकल न्यायाधीश ने यह भी पाया कि उत्तरदाता के मामले पर एक ही पद पर पदोन्नति के लिए 24 अप्रैल, 1989 और 3 सितंबर, 1992 को दो बार फिर से विचार किया जाना था और हालांकि इस हद तक उनके मामले पर 1 मार्च, 1989 को प्रसारित पदोन्नति नीति (अनुलग्नक पी-2) के तहत सही तरीके से विचार किया गया था, विभागीय पदोन्नति समिति फिर से गलत हो गई थी क्योंकि उत्तरदाता के मामले का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष के लिए, प्रासंगिक तिथियों के संदर्भ में, अलग-अलग अभिलेख का उचित मूल्यांकन किए बिना एक ही तरीके से किया गया था और मूल्यांकन वास्तव में दोनों वर्षों के लिए एक ही समय पर किया गया था। हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तरदाता के इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसके मामले में एक साक्षात्कार की परिकल्पना नहीं की गई थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नीति अनुलग्नक पी-1 के स्पष्ट शब्दों पर भरोसा किया गया था। विद्वान एकल

न्यायाधीश ने तब यह निर्णय दिया कि नवंबर, 1992 से 16 जून, 1993 की अवधि के लिए उत्तरदाता के वेतन को रोकना अन्यायपूर्ण था और इस तथ्य के आलोक में कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी S.L.P. No. 1707-08 of 1993, का निपटारा करते हुए कहा था कि उत्तरदाता की हैदराबाद में पोस्टिंग उचित नहीं थी और इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तरदाता 8 नवंबर, 1992 से 16 जून, 1993 तक बिना किसी औचित्य के कर्तव्य से अनुपस्थित था। इस दावे की भी अनुमति दी गई और अनुलग्नक पी-5 और पी-8 को तदनुसार रद्द कर दिया गया। विद्वत एकल न्यायाधीश के इस फैसले के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई है, जबकि उत्तरदाता द्वारा प्रति-आपत्तियां दायर की गई हैं और साथ ही उनके खिलाफ तय किए गए प्रश्नों पर विद्वत एकल न्यायाधीश के फैसले पर आपत्ति जताई गई है।

(4) हमने अपीलरथी कि और से श्री अशोक अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता और उत्तरदाता कि और से श्री डी.सी. अग्रवाल को अच्छे से सुन लिया है। श्री अशोक अग्रवाल ने तर्क दिया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि बैंक की पदोन्नति नीति के तहत 1 अगस्त, 1984 और 1 अगस्त, 1988 के बीच चार तिथियों पर शीर्ष कार्यकारी स्केल ग्रेड VII (टी. ई. जी. VII) में पदोन्नति के लिए उत्तरदाता का मामला, दिनांक 1 1 मार्च, 1989, पूर्वव्यापी रूप से नहीं किया जा सकता था, एक तथ्यात्मक त्रुटि पर आधारित था। इस संबंध में उन्होंने इंगित किया है कि अपीलकर्ता-बैंक में वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति, जिसमें उत्तरदाता का मामला भी शामिल है, पर 23 फरवरी, 1984 की नीति द्वारा संशोधित नीति अनुलग्नक पी-1 के संदर्भ में विचार किया जाना था, जिसे 1998 के सी. एम. संख्या 1142 के साथ अनुलग्नक ए-2 के रूप में जोड़ा गया था और जैसा कि मूल्यांकन, वास्तव में, नीति अनुलग्नक ए-2 के संदर्भ में किया गया था, विद्वान एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष गलत था। इस संबंध में उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि यद्यपि नीति अनुलग्नक ए-2 की एक प्रति विशाल अभिलेख में थी जो विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह नोटिस से बच गई है। दूसरी ओर उत्तरदाता ने बताया है कि इस नीति को पहली बार पूर्व-उल्लिखित *नागरिक* विविध आवेदन के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखा गया था और इस तरह, अब इसे नहीं देखा जा सकता है। हमने इस मुद्दे पर पक्षों को भी सुना है। यह सच है कि 1984 की नीति (अनुलग्नक ए-2) को किसी भी पक्ष की दलीलों में स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है कि यह नीति मौजूद है और पदोन्नति के लिए उत्तरदाता के मामले को नियंत्रित करती है। इसलिए, हमारी राय है कि इसे ध्यान में रखना न्याय के हित में होगा। श्री अशोक अग्रवाल के तर्क की इस पृष्ठभूमि में जांच की जानी चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टी. ई. जी. स्केल VII में पदोन्नति के लिए उत्तरदाता के मामले की जांच चार अलग-अलग तिथियों के संदर्भ में की जानी थी। 1अगस्त, 1984,20 फरवरी, 1986, 8 जून, 1987 और 1
अगस्त, 1988 और उसके बाद 24 अप्रैल, 1989 और 3 फरवरी, 1992 को।इसलिए, यह स्पष्ट है कि पहले चार आकलन नीति अनुलग्नक ए-2, दिनांक 23 फरवरी, 1984 की शर्तों के तहत किए जाने थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया है कि पदोन्नति के लिए उत्तरदाता के मामले पर एक विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया था, जिसकी परिकल्पना पहली बार 1989 की नीति के तहत की गई थी।तथापि, हमारी राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष को कायम नहीं रखा जा सकता है। 1982 की नीति के अवलोकन से पता चलता है कि पैराग्राफ 1 से 4 में स्केल V और स्केल VI (बाद में स्केल VI और VII के रूप में संशोधित) में पदोन्नति के लिए 28 नवंबर, 1975,13 सितंबर, 1978,8 सितंबर, 1978 और 14 अगस्त, 1981 के निर्देश I के तहत प्रदान की गई पदोन्नति के लिए मौजूदा प्रक्रिया को दोहराया गया था, जिसमें यह

बताया गया था कि अधिकारी का पिछला प्रदर्शन उसके ए. सी. आर. के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और उच्च जिम्मेदारियों को संभालने की उसकी क्षमता का मूल्यांकन प्रबंध निदेशक द्वारा आयोजित एक अनौपचारिक साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, और बैंक की केंद्रीय प्रबंधन समिति के किसी भी एक या अधिक सदस्यों का मूल्यांकन किया जाएगा।हालांकि, पैराग्राफ 5 के बाद एक नई प्रक्रिया की परिकल्पना की गई कि इन दोनों पहलुओं का अब केंद्रीय समिति द्वारा अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा और चूंकि ग्रेड V और ग्रेड VI में पदोन्नति बहुत वरिष्ठ स्तर की पदोन्नति थी और उच्च स्तर की दक्षता की आवश्यकता थी, इसलिए यह उचित था कि एक अधिकारी जो पिछले प्रदर्शन के मूल्यांकन या साक्षात्कार में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असमर्थ था, उसे पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।यह भी सुझाव दिया गया कि पहले परिकल्पित अनौपचारिक साक्षात्कार के बजाय, एक संरचित साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा जिसमें नीति में उल्लिखित (आठ) या दस संकेतों के संबंध में उपयुक्त प्रश्न पूछे जाएंगे।इस नीति को 23 फरवरी, 1984 (अनुलग्नक ए-2) की नीति द्वारा संशोधित किया गया था और एक संरचित अंतराल प्रणाली को बनाए रखते हुए, अब 8 के बजाय 14 संकेतकों का सुझाव दिया गया था, और टी. ई. जी. स्केल V और उससे ऊपर की पदोन्नति एक विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की जाएगी जिसमें अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के नामांकित व्यक्ति शामिल होंगे और यह निकाय ही था जो अंतिम निकाय, यानी बैंक के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति में पदोन्नति के लिए नामों की सिफारिश करेगा।इस प्रक्रिया को व्यापक रूप से 1989 की नीति के तहत भी बनाए रखा गया था।

(हरजीत सिंह बेदी, जे.)

(अनुलग्नक पी-2) में कहा गया है कि एक अधिकारी जो अपने पिछले प्रदर्शन के मूल्यांकन में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असमर्थ था, उसे इस अवधि के लिए नहीं बुलाया जाएगा।ऊपर दिए गए तथ्यों के सारांश से यह स्पष्ट है कि 1 अगस्त, 1984 और 1 अगस्त, 1988 के बीच पदोन्नति के लिए उत्तरदाता के मामले पर 1982 की पदोन्नति नीति (अनुलग्नक पी1) में निर्धारित मापदंडों के आलोक में विचार किया जाना था, जैसा कि 1984 की नीति (अनुलग्नक ए-2) द्वारा संशोधित किया गया था।मामले के इस दृष्टिकोण में, दाविद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि 1989 की नीति को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, हालांकि कानूनी रूप से सही है, तथ्यों के गलत मूल्यांकन पर आधारित है।

(5) वास्तव में, उत्तरदाता के मामले में यह विचार 1982 और 1984 की नीति के तहत किया गया था और यदि ऐसा है, तो क्या मूल्यांकन उसके तहत प्रदान किए गए मापदंडों के अनुसार था।हमारे पास इस संबंध में 4 सितंबर, 1993 के परिशिष्ट ए-3 का अवलोकन किया गया है, जो टी. ई. जी. स्केल VII में उत्तरदाता की पदोन्नति के संबंध में उस तारीख को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त हैं। समिति ने नोट किया कि प्रत्येक क्षेत्र में साक्षात्कार और पिछले प्रदर्शन में अंकों का योग्यता प्रतिशत 60 प्रतिशत था और चूंकि उत्तरदाता 21 जुलाई, 1981 से 12 नवंबर, 1987 तक निलंबित था, इसलिए 21 जुलाई, 1981 तक की रिपोर्टों को उनके पिछले प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में उसी तरह से ध्यान में रखा जाएगा जैसे अन्य योग्य अधिकारियों के लिए किया गया था।इसके बाद समिति ने प्रत्येक वर्ष के लिए मूल्यांकन किया।समिति ने पहली बार 1 अगस्त, 1984 को पदोन्नति के लिए उत्तरदाता के मामले पर विचार किया और कहा कि "प्रदर्शन मूल्यांकन" और "क्षमता के मूल्यांकन के लिए साक्षात्कार" शीर्ष के तहत अलग से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक था और जबकि उसे "प्रदर्शन मूल्यांकन" शीर्ष के तहत 60 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे, उसने साक्षात्कार में केवल 25.7% अंक प्राप्त

किए थे जो निर्धारित 60 प्रतिशत योग्यता अंक से बहुत कम थे।यह भी बताया गया कि 1 अगस्त, 1984 से प्रभावी पदोन्नति के लिए जिन 52 अधिकारियों का साक्षात्कार लिया गया था, उनमें से नौ अधिकारी साक्षात्कार में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहे थे, जबकि योग्यता में सबसे कम अधिकारी, जिसे वास्तव में पदोन्नत किया गया था, ने "प्रदर्शन मूल्यांकन" में 70 प्रतिशत अंक और साक्षात्कार में 66 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे, जो कुल मिलाकर 200 में से 136 अंक थे।समिति ने 20 फरवरी, 1986 को विचारित पदोन्नति के संबंध में भी इसी तरह का मूल्यांकन किया। 8जून, 1987,1 अगस्त, 1988,24 अप्रैल, 1989 और 3 फरवरी, 1992।हम यह भी पाते हैं कि जिस स्थिति में अपीलार्थी-बैंक और उत्तरदाता को रखा गया था, उसी स्थिति में साक्षात्कार समिति के पास उत्तरदाता के मामले पर एक साथ विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।यह दोहराया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अगस्त, 1993 के अपने आदेश (वी. महादेवन और अन्य बनाम डी. सी. अग्रवाल[3]) में स्पष्ट रूप *से* निर्देश *दिया था कि* पदोन्नति के *मामले* पर एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा जो उस तारीख से तीन सप्ताह के भीतर गठित की जाएगी।इस स्थिति में अंतर-1 समीक्षा समिति ने 1 सितंबर, 1993 को आयोजित अपनी बैठक में अपना मूल्यांकन किया था (अनुलग्नक आर-2) और इन सिफारिशों को 7 सितंबर, 1993 को निदेशक पदोन्नति समिति द्वारा भी अनुमोदित किया गया था (अनुलग्नक आर-3) और उसी तारीख को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।इस स्थिति का सामना करते हुए, उत्तरदाता ने अपनी क्रॉस आपत्तियों की ओर रुख किया है और तर्क दिया है कि चूंकि उन्हें 27 जुलाई, 1980 से टी. ई. जी. स्केल VI में पदोन्नत किया गया था, इसलिए उन्हें वर्ष 1993 में उसी पद के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता था।^उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि चूंकि वे 1981 से 1987 तक निलंबित थे, इसलिए पदोन्नति के उद्देश्य से उनके रिकॉर्ड का उचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था।श्री अशोक अग्रवाल ने हालांकि आग्रह किया है कि उत्तरदाता ने कहीं भी यह दलील नहीं दी थी कि उन्हें साक्षात्कार के अधीन नहीं किया जा सकता है और वास्तव में, उन्होंने केवल समिति के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें।उन्होंने यह भी बताया है कि साक्षात्कार 17 अगस्त, 1993 को दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया था, जिसे महादेवन और अन्य बनाम *डी. सी. अग्रवाल* (सुप्रा) के रूप में रिपोर्ट किया गया था, हमने इस संबंध में पक्षों को भी सुना है।उत्तरदाता को पहले टी. ई. जी. ग्रेड VI में पदोन्नत किया गया था, जबकि अब विचाराधीन पदोन्नति टी. ई. जी. ग्रेड VII में थी। यह भी महत्वपूर्ण है कि 1982,1984 और 1989 की पदोन्नति नीतियों को कोई चुनौती नहीं है।जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, उपर्युक्त नीतियों में विशेष रूप से एक उम्मीदवार के पिछले प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए उसके ए. सी. आर. और एक साक्षात्कार में उसके प्रदर्शन के आधार पर उच्च जिम्मेदारी के लिए उसकी क्षमता का प्रावधान किया गया था, जो 1982 से पहले एक अनौपचारिक होना था, और

1982 के बाद, आठ (1982 की नीति) और उसके बाद 14 (1984 की नीति) के आधार पर एक समिति के समक्ष एक संरचित और औपचारिक साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा।इसके अलावा, 17 अगस्त, 1993 के अपने फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (और पृष्ठ 3 पर उद्धृत) ने पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (ii) में स्पष्ट रूप से कहा था कि बैंक प्रासंगिक नीतियों के तहत पदोन्नति के लिए उत्तरदाता के मामले पर विचार करेगा, जिस तरह से अन्य अधिकारियों का मूल्यांकन किया गया था।

(6) उत्तरदाता ने इस स्थिति में तर्क दिया है कि एक पल के लिए यह मानते हुए भी कि नियमों के तहत एक हस्तक्षेप की परिकल्पना की गई थी, उनके मामले में कोई साक्षात्कार नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह

[3]A.I.R. 1994 S.C. 961

1981 से 1987 तक निलंबन में थे।हमारी राय है कि इस तर्क का कोई आधार नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने ऊपर निर्दिष्ट आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि उत्तरदाता के साथ उनके सहयोगियों के बराबर व्यवहार किया जाना चाहिए, जिन्हें पहले पदोन्नत किया गया था।

(7) श्री अशोक अग्रवाल ने तब तर्क दिया कि उत्तरदाता ने साक्षात्कार में 25.7% अंक प्राप्त किए थे और चूंकि यह पदोन्नति की नीतियों के तहत निर्धारित 60 प्रतिशत योग्यता अंकों से काफी कम था, इसलिए उत्तरदाता किसी भी मामले में सफल नहीं हो सका। उन्होंने यह भी बताया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि 1982 और 1984 की नीतियों में उल्लिखित विभिन्न संकेतों के आलोक में उत्तरदाता की योग्यता का उचित मूल्यांकन करने में साक्षात्कार समिति की विफलता गलत थी। उन्होंने आग्रह किया है कि उत्तरदाता ने साक्षात्कार को विफल करने का जानबूझकर प्रयास किया था और इस तरह, समिति ने उत्तरदाता से केवल तीन प्रश्न पूछने को पूरी तरह से उचित ठहराया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि साक्षात्कार समिति के किसी भी सदस्य के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी का कोई आरोप नहीं था और इस स्थिति में, इन कार्यवाही के लिए कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। हालाँकि, उत्तरदाता ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया है कि हालाँकि 14 अलग-अलग संकेतों पर एक साक्षात्कार के लिए प्रदान की गई नीति, उत्तरदाता से पूछे गए प्रश्नों ने शायद ही उनमें से किसी को संतुष्ट किया हो। हमने 1 सितंबर, 1993 को शाम 4:40 बजे से शाम 5:45 बजे के बीच आयोजित साक्षात्कार के कार्यवृत्त को देखा है और उत्तर के साथ अनुलग्नक आर-2 के रूप में जोड़ा है।समिति ने ध्यान दिया कि उत्तरदाता का मूल्यांकन नीचे दिए गए 14 मापदंडों पर किया जाना थाः—

1. निगमित लक्ष्यों और उद्देश्यों का ज्ञान।
2. भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण के प्रति जागरूकता।
3. संगठन की बदलती जरूरतों के अनुकूलता।
4. आत्म-विश्वास।
5. उपलब्धि प्रेरणा।
6. भावनात्मक स्थिरता
7. उत्पादकता और दक्षता के लिए चिंता
8. पहल और रचनात्मकता
9. विश्लेषणात्मक कौशल और निर्णय लेने की क्षमता।
10. योजना और संगठन क्षमताएँ।
11. अंतर-व्यक्तिगत और टीम निर्माण कौशल।
12. जनसंपर्क कौशल।
13. संचार में प्रभावशीलता
14. कर्मचारियों का विकास।

8. कार्यवाही के पैराग्राफ 2 में, यह कहा गया है कि सुखद आदान-प्रदान के बाद, समिति के सदस्यों ने औपचारिक बातचीत शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन उत्तरदाता इस बात पर जोर दे रहा था कि उसे अपने मामले और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर कुछ स्पष्टीकरण दिए जाने चाहिए और उसने समिति के सदस्यों को अप्रासंगिक मुद्दे उठाकर साक्षात्कार के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी थी।समिति ने तब तीन प्रश्न पूछे थे और उनके उत्तर प्राप्त किए थे।इन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः—

"(i) पिछले दो-तीन महीनों से उप महाप्रबंधक, चंडीगढ़, मुख्य शाखा के रूप में उनकी वर्तमान जिम्मेदारी और विशिष्ट उपलब्धियां क्या हैं?

श्री अग्रवाल ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और अप्रासंगिक बिंदुओं को लाकर सवाल से बचने

की कोशिश कर रहे थे।

(ii) नरसिम्हम समिति की बुनियादी सिफारिशें क्या हैं?

श्री अग्रवाल बार-बार पूछताछ के बावजूद, एस. एल. आर. के बारे में एक आइटम के रूप में उल्लेख करने के अलावा कोई विशिष्ट बिंदु नहीं दे सके।लेकिन वह यह नहीं बता सके कि किस हद तक और किस समय सीमा के भीतर एस. एल. आर. को कम करने की सिफारिश की गई थी।संयोग से, उन्होंने उल्लेख किया कि नरसिम्हम समिति की सिफारिशें कर सुधारों पर थीं।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित पिछली ऋण नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

श्री अग्रवाल कोई जवाब देने में विफल रहे।''

समिति ने फिर यह रिकॉर्ड किया कि उत्तरदाता कुछ कागजात लाना चाहते थे और समिति को कुछ पत्र प्रस्तुत करना चाहते थे, जिनकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी और अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि वे साक्षात्कार के बारे में गंभीर नहीं थे और उनकी समझ और जागरूकता का स्तर और पदोन्नति के लिए उनकी क्षमता भी वांछित स्तर से बहुत कम थी। हमारी राय है कि मिनटों में दर्ज किए गए अंतराल का पाठ्यक्रम दो संभावनाओं का सुझाव देता हैःपहला, कि प्रत्यर्थी, बैंकिंग उद्योग में 30 से अधिक वर्षों तक सेवा करने के बावजूद, इसके मूल सिद्धांतों से पूरी तरह से अनजान था और दूसरा, कि उसने साक्षात्कार को रोकने के लिए जानबूझकर प्रयास किया था। हमारे विचार से, इन दोनों में से कोई भी संभावना उत्तरदाता के मामले को नष्ट कर देती है, लेकिन दूसरा अधिक प्रशंसनीय प्रतीत होता है। हमारे विचार को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से समर्थन मिलता है और स्वयं उत्तरदाता द्वारा उन पर भरोसा किया जाता है। उत्तरदाता ने 1 सितंबर, 1993 की एक नोट तिथि दर्ज की है, जिसे उन्होंने समीक्षा समिति के सदस्यों के लिए तैयार किया था (हालांकि उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था) और जिसे उन्होंने तब मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक) को निजी सचिव को सौंप दिया था और 15 सितंबर, 1993 को उनके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय कार्यालय, बॉम्बे के अध्यक्ष को भेजा गया एक टेलेक्स संदेश।चूँकि साक्षात्कार भी 1 सितंबर, 1993 को आयोजित किया गया था, इसलिए पहला नोट स्वयं उत्तरदाता द्वारा बनाया गया एक समकालीन दस्तावेज है। हम यहाँ दो दस्तावेजों को पुनः प्रस्तुत करते हैंः—

''सेवा मे,

डी. सी. अग्रवाल, डी. महाप्रबंधक (एस. बी. आई)
शिविरःएस. बी. आई.,

केंद्रीय कार्यालय, बॉम्बे।

1 सितंबर, 1993

माननीय साक्षात्कार समिति के सदस्यों के लिए टिप्पणी

जनरल एम एनागर ग्रेड (VII) में पदोन्नति के लिए विषय विचार

इसमें माननीय सदस्यों के साथ अनौपचारिक चर्चा का संदर्भ है।

2. जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, मुझे 30 अगस्त, 1993 को केंद्रीय कार्यालय से 25 अगस्त, 1993 के मेरे फैक्स संदेश का जवाब मिला (संलग्न प्रति व्यक्तिगत रूप से सौंपी गई) जिसमें मुझे महाप्रबंधक श्रेणी के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष मेरा मामला इसके लिए है।

मुख्य महाप्रबंधक श्रेणी में पदोन्नति और नियुक्ति जिसमें मेरे कनिष्ठ जनवरी, 1992 से काम कर रहे हैं।

3. बहुत सम्मान के साथ मैं आपको भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 17 अगस्त, 1993 के हाल के फैसले की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं।विशेष रूप से मैं निर्देश संख्या II और III की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं:—

निर्देश (ii)-हम इस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं कि क्या उच्च स्तर के लिए साक्षात्कार आवश्यक है और क्या उत्तरदाता को बढ़ावा नहीं देने के लिए कोई वैध औचित्य था जिसका इन कार्यवाही से पहले का रिकॉर्ड बेदाग है।लेकिन अगर नियम अनुमति देते हैं तो समिति का गठन किया जाता है।

निर्देश (iii)-(उक्त) समिति का गठन आज से तीन सप्ताह के भीतर किया जाएगा जो यह तय करेगी कि क्या उत्तरदाता (यानी डी. सी. अग्रवाल) उच्च स्तर पर पदोन्नत होने का हकदार था जिसमें उसके कनिष्ठ अधिकारी काम कर रहे हैं।

4. *ऊपर से आप देखेंगे कि मेरे कनिष्ठ पहले से ही 30 जनवरी, 1991 से मुख्य महाप्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए इस माननीय समिति को सी. जी. एम. के लिए मेरी पात्रता तय करनी है। स्केल अर्थात शीर्ष कार्यकारी ग्रेड (विशेष स्केल-I) और टी. ई. जी. VII के लिए नहीं जिसके लिए नियमों में कोई औपचारिक साक्षात्कार निर्धारित नहीं है।*

5. *ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार फिर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और निर्देशों की उसी तरह गलत व्याख्या की गई है जिस तरह से बैंक ने अपने सक्षम कानूनी दिग्गजों द्वारा निर्देशित "अनुशासनात्मक कार्यवाही के पुनरुद्धार" पर निर्णय लिया था-28 दिसंबर, 1982 के नोटिस के माध्यम से।यह कदम एक निर्दोष त्रुटि नहीं थी, बल्कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचने और उस उद्देश्य को प्राप्त करने का एक जानबूझकर प्रयास था जिसे वे अदालतों के समक्ष सफल करने में* विफल रहे।बैंक इस बात से पूरी तरह अवगत था कि अनुशासनात्मक कार्रवाई को "पुनर्जीवित" करने की स्वतंत्रता देने के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष की गई प्रार्थना को उच्च न्यायालय द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील में खारिज कर दिया गया था और विशेष अनुमति याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था (कृपया एल. पी. ए. और एस. एल. पी. में अपील के आधार का उल्लेख करें)।बैंक की इस कार्रवाई पर उच्च न्यायालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी, जो एक अंतरिम आदेश *पारित करने* के लिए विवश था कि प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनाया गया था। दोनों प्रबंध निदेशकों को बाद में आउट एंड रूल निसी जारी किया गया जब दोनों एम. डी.उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए, शीर्ष न्यायालय ने एक बार फिर बैंक के उक्त पुनरुद्धार नोटिस को रद्द कर दिया था।

6.	XX	XX	XX
7.	XX	XX	XX
8.	XX	XXX	XX
9.	XXX	XX	XX
10.	XX	XX	XXX
11.	XX	XX	XX

डी. सी. अग्रवाल
डी. महाप्रबंधक,
टी. ई. जी. VI

मैं यह भी बता सकता हूं कि साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों ने मुझे मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक) श्री दांडेकर के माध्यम से सलाह दी कि मुझे अपने संक्षिप्त मामले में मेरे द्वारा की गई उपलब्धियों के महत्वपूर्ण कागजात आदि लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्यों ने मुझे यह भी सलाह दी कि शीर्ष प्रबंधन की ओर से उन्हें केवल टी. ई. जी. स्केल VII के लिए मेरा साक्षात्कार करने का आदेश दिया गया था और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ-साथ उस तारीख के बारे में भी पता नहीं था जिससे टी. ई. जी. VII के रूप में पदोन्नति पर विचार किया जाना था।माननीय सदस्यों ने उस नोट के साथ-साथ फैक्स संदेश को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया जो मैंने पहले डिप्टी गवर्नर को भेजा था। एम. डी. (कार्मिक)।

एसडी/-

डी. सी. अग्रवाल''

(10) यह एक स्पष्ट है कि यह दस्तावेज़, जो मूल रूप से पैराग्राफ 11 पर समाप्त होता है, लेकिन साक्षात्कार समिति के सदस्यों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने के बाद उत्तरदाता द्वारा एक पोस्टस्क्रिप्ट स्पष्ट रूप से जोड़ा गया था। 15 सितंबर, 1993 का टेलेक्स संदेश भी उतना ही स्पष्ट है कि जिस तरीके से उत्तरदाता ने साक्षात्कार समिति के समक्ष अपना आचरण किया था। इस दस्तावेज़ को विस्तार से नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

15 सितंबर, 1993 का टेलीक्स संदेश

''सेवा मे,

श्री डी. बसु, अध्यक्ष,

भारतीय स्टेट बैंक,

केंद्रीय कार्यालय, बॉम्बे।

आवेदन करता,

श्री डी. सी. अग्रवाल,
डी. महाप्रबंधक,
भारतीय स्टेट बैंक,
सेक्टर 17, मुख्य शाखा, चंडीगढ़

साहब,

अगर मैं 2 सितंबर, 1993 को मुझे श्रोता प्रदान करके आपका मूल्यवान समय देने के लिए आपको

धन्यवाद नहीं देता हूं तो मैं अपने कर्तव्य में विफल हो *जाऊंगा। मैंने आपको संक्षेप में बताया था कि पिछले दिन यानी 1 सितंबर, 1993 को तीन उप प्रबंध निदेशकों का साक्षात्कार कुछ स्पष्टीकरणों के अभाव में नहीं हो सका था, जो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जिस श्रेणी के लिए मेरा साक्षात्कार किया जाना था, उसके संबंध में आवश्यक थे। समिति के* सदस्यों ने मुझे बताया था कि वे केवल टी. ई. जी. एस.-VII के लिए साक्षात्कार से संबंधित थे और वे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों से अवगत नहीं थे। यहाँ तक कि विद्वान सदस्यों को भी उस तारीख के बारे में पता नहीं था जिससे टीईजीएस-VII के लिए पदोन्नति पर विचार किया जा रहा था। इस स्तर पर मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक) श्री एम. एन. दांडेकर को बुलाया गया, जिन्होंने यह भी कहा कि वे मेरे द्वारा वांछित स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे। फिर, समिति की अध्यक्ष श्री सुप्रिया गुप्ता, उप प्रबंध निदेशक (वाणिज्यिक बैंकिंग) ने कहा, ''ठीक है, हम कहेंगे कि डी. सी. अग्रवाल द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण के अभाव में साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जा सका।'' दूसरे सदस्य श्री एन. एम. चोरिडिया ने एक और टिप्पणी की, ''हम कहेंगे कि आपने भाग नहीं लिया और साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जा सका।तीसरे सदस्य ने केवल इतना कहा कि हम कानूनी स्थिति से अवगत नहीं हैं। इसलिए साक्षात्कार नहीं हुआ।इस आशय का एक पत्र मेरे द्वारा पी. एस. को मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक) को विधिवत स्वीकार किया गया था, उसी दिन जब मैं उप प्रबंध निदेशक (कार्मिक) श्री एन. जी. पिल्लई से मिला था, तो मैंने अनौपचारिक रूप से उनसे कहा था कि इसी कारण से साक्षात्कार नहीं हो सकता है। मैंने नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा मेरे साथ किए *जा रहे* दुर्भावनापूर्ण व्यवहार को भी उनके संज्ञान में लाया ताकि किसी तरह मेरे खिलाफ कुछ रिकॉर्ड बनाया जा सके ताकि इसका उपयोग मेरे खिलाफ समिति द्वारा किया जा सके जो सेवा में विस्तार के लिए मेरे मामले पर विचार कर रही थी।मैं आपके ध्यान में एक डी. ओ. पत्र नं. जी. एम. ओ./83, दिनांक 25 अगस्त, 1993 को महाप्रबंधक (संचालन) से भाषा की अवधि और विषय-वस्तु ने मुझे बहुत हैरान कर दिया था।

2. हालांकि, बैंक के पत्र नं. जी. एम. ओ./सी. बी. सी./11276, दिनांक 8 सितंबर, 1993, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मैंने 60 प्रतिशत योग्यता अंकों के बजाय इंटरवी आई. ई. डब्ल्यू. में 25.7% अंक प्राप्त किए।यह स्थिति सही नहीं है।मैं इस प्रभाव के लिए एक शपथ पत्र की शपथ ले रहा हूं। अगर मैं बिना साक्षात्कार के 25.7% प्राप्त कर सकता हूं, तो सबसे विनम्रता से मैं 100% अंकों के करीब पहुंच जाता अगर साक्षात्कार वास्तव में हुआ होता।

मैं उपरोक्त तथ्यों को आपके संज्ञान में लाना उचित समझता हूं।

सादर नमन के साथ,

डी. सी. अग्रवाल''

(11) ये दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से संवाददाता कि मनोदशा का खुलासा करते हैं और जब बैठक के कार्यवृत्त के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनका इरादा कभी भी साक्षात्कार के समक्ष समर्पण करने का नहीं था, बल्कि विलंभ करने और अंततः इसे रद्द करने का था। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तरदाता को स्वभाव से ''उत्तेजक'' पाया था, एक ऐसी टिप्पणी जिसके साथ हम दिल से सहमत हैं, लेकिन कई दिनों तक उसे सुनने के बाद, हम उसे एक बेहद मुखर और बुद्धिमान व्यक्ति भी पाते हैं। इसलिए, हम आश्वस्त हैं कि उत्तरदाता अपनी

कार्रवाइयों के परिणामों के बारे में पूरी तरह से अवगत था। इसलिए, अंतर्वर्ती समिति को उनकी हठधर्मिता के कारण साक्षात्कार को छोटा करने में पूरी तरह से न्यायोचित ठहराया गया। यह भी स्पष्ट है कि 1 सितंबर, 1993 का दस्तावेज़ उत्तरदाता द्वारा साक्षात्कार के लिए जाने से पहले तैयार किया गया था और उस समय क्या आवश्यक था, इस बारे में उनकी धारणा उसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।हमारे विचार से, कार्यवृत्त इस बात का एक विश्वसनीय अभिलेख है कि क्या हुआ था।फिर भी समिति ने निर्धारित 14 संकेतकों पर अंक दिए थे।यह सच है, जैसा कि तर्क दिया गया है कि उत्तरदाता से पूछे गए प्रश्न सभी 14 निर्धारित मापदंडों की पर्याप्त पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हमारी राय है कि पहले से दर्ज कारणों से, कि उत्तरदाता स्वयं इस स्थिति के लिए जिम्मेदार था। श्री अशोक अग्रवाल का बैंक ऑफ इंडिया बनाम अपूर्बा कुमार साहा[4] मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *फैसले पर भरोसा* इस *प्रकार पूरी तरह* से उचित है। यह भी एक बैंक कर्मचारी का मामला था जिसने अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपना बचाव करने के लिए उसे दिए गए कई अवसरों का लाभ उठाने से इनकार कर दिया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे कर्मचारी ने बाद के चरण में यह दावा करने का अपना अधिकार खो दिया था कि अनुशासनात्मक कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के रूप में दूषित हो गई थी। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होती हैं। उत्तरदाता ने हस्तक्षेप के समय तुच्छ आपत्तियां उठाई थीं, जाहिरा तौर पर वह अपनी कार्यवाही में शामिल होने के मूड में नहीं था और इस स्थिति में वह अब शिकायत नहीं कर सकता कि साक्षात्कार समिति ने उसका उचित मूल्यांकन नहीं किया था। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि समिति भारतीय स्टेट बैंक के तीन उप महाप्रबंधकों की थी और उनमें से किसी के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।हमने ऊपर उल्लिखित 14 संकेतकों के संबंध में किए गए वास्तविक मूल्यांकन को भी देखा है और पाया है कि प्रत्येक व्यक्तिगत पैरामीटर के लिए अंक दिए गए हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि मूल्यांकन 8 जून, 1982 की नीति में उल्लिखित विभिन्न संकेतों के अनुसार नहीं किया गया था, इसलिए सही नहीं है।

(12) उत्तरदाता ने इस बात पर भी बहुत जोर दिया कि अपीलार्थी-बैंक के अधिकारी बैंक और उसके अधिकारियों को बार-बार अदालत में ले जाने की हिम्मत रखने के लिए उनके खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे और यह कि यह संस्थागत पूर्वाग्रह उनके पदोन्नति के मामले में दिखाई दिया था। इस संबंध में, इस न्यायालय के 1989 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 15874 में 9 अप्रैल, 1991 (डी. सी. अग्रवाल बनाम भारतीय स्टेट बैंक) (सुप्रा के रूप में *सूचित)* के निर्णय *के साथ-साथ 30 मई,* 1985 को श्री रस्तोगी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें बैंक के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी। तदनुसार उत्तरदाता द्वारा यह आग्रह किया गया है कि चूंकि लेटर पेटेंट अपील और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को भी खारिज कर दिया गया था, इसलिए ये टिप्पणियां अंतिम थीं। श्री अशोक अग्रवाल ने हालांकि बताया है कि जांच अधिकारी द्वारा किए गए पक्षपातपूर्ण और अनुचित व्यवहार को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और 13 अक्टूबर, 1992 को तय की गई 1992 की सिविल अपील संख्या 4213 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कोई और भरोसा नहीं रखा गया है, *भारतीय स्टेट बैंक और अन्य* बनाम *डी. सी. अग्रवाल और* अन्य[5], एस. एल. पी. ने विद्वान एकल न्यायाधीश और इस न्यायालय की लेटर्स पेटेंट बेंच के आदेश के खिलाफ बैंक द्वारा दायर किया था। हम इस फैसले को पढ़ने से पाते हैं कि हालांकि बैंक द्वारा विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के दौरान उत्तरदाता को केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट की आपूर्ति न करने के परिणामों के संबंध में केवल सीमित मुद्दे पर अपना निर्णय

[4] 1994 (1) S.L.R. 260,
[5] 1993 (1) S.C.C. 13.

आधारित किया था। इसलिए, उत्तरदाता के लिए यह आग्रह करने के लिए खुला नहीं है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए पूर्वाग्रह के निष्कर्ष का माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समर्थन किया गया था। हम मानवीय कमजोरियों से अनजान नहीं हो सकते हैं, और बैंक में अपने वरिष्ठों के प्रति उत्तरदाता का अपमानजनक व्यवहार, विशेष रूप से उन लोगों के प्रति जो वह शत्रुतापूर्ण मानते थे और अन्य जो किसी स्तर पर उनके कनिष्ठ हो सकते थे, उनके प्रति उनके रवैये को प्रभावित कर सकते थे और यह निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से था जिसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें उत्तरदाता के पक्ष में आदेश देने के लिए प्रेरित किया था और साथ ही संबंधित अपील भी। हमारी यह राय है कि चूंकि उत्तरदाता की पदोन्नति के मामले पर बैंक के कुछ वरिष्ठ सदस्यों द्वारा विचार किया गया था और चूंकि उनमें से किसी को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए संस्थागत पूर्वाग्रह का व्यापक आरोप स्वीकार्य नहीं है।

(13) इसमें यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाता नवंबर, 1992 से 16 जून, 1993 तक वेतन के भुगतान का हकदार था, इस तथ्य के बावजूद कि वह हैदराबाद स्थानांतरित होने पर कर्तव्य में शामिल नहीं हुआ था, यह भी गलत था क्योंकि उत्तरदाता ने उसे दिए गए आदेशों की अवज्ञा की थी। हालाँकि, यह तर्क हमारे लिए उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने S.L.P. No. 1707-08 of 1993. (वी. महादेवन और एक अन्य *बनाम डी. सी.अग्रवाल*[6] *मे पहले* ही कहा था कि उत्तरदाता की हैदराबाद में पोस्टिंग उचित नहीं थी और इसी कारण से उन्हें फिर से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि वेतन के भुगतान के लिए उत्तरदाता का दावा पूरी तरह से न्यायसंगत था। इसलिए, हमारी राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

(14) इसलिए, 1998 का एल. पी. ए. सं. 364 आंशिक रूप से अनुमत है, 8 सितंबर, 1993 के आदेश अनुलग्नक पी-8 को रद्द करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया *गया* है, जहां इसे 27 मई, 1993 के अनुलग्नक पी-5 के संबंध में निष्कर्ष के रूप में रखा गया है। 1999 के एल. पी. ए. सं. 80 के रूप में पंजीकृत क्रॉस आपत्तियाँ/अपील भी खारिज कर दी जाती हैं।

1998 का पत्र पेटेंट अपील सं. 365 और 1999 का क्रॉस उद्देश्य 'एन/एल. पी. ए. सं. 81

(15) अपीलार्थी-बैंक में उत्तरदाता के कार्यकाल से संबंधित तथ्य ऊपर दिए गए हैं और उन्हें पूरी तरह से दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

(16) इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 9 अप्रैल, 1991 को 1989 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 15874 डी. सी. ए. एल. अग्रवाल बनाम भारतीय स्टेट बैंक (सुप्रा) *में बैंक द्वारा दिए गए दंड के आदेश को* रद्द करने के बाद, मामले को लेटर पेटेंट बेंच में ले जाया गया। बैंक ने भी 15 मई, 1991 को अपील को खारिज कर दी और उच्चतम न्यायालय ने एस. एल. पी. को अनुमति दी, लेकिन अंततः 13 अक्टूबर, 1992 को *भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम* डी. *सी. अग्रवाल और एक* अन्य (सुप्रा) की अपील को खारिज कर दिया, उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद उत्तरदाता को एक नई विभागीय जांच शुरू करने के लिए 28 दिसंबर, 1992 का नोटिस दिया गया था। इसके बाद उत्तरदाता ने इस न्यायालय में 1992 का 1098 नंबर दायर किया जिसमें अवमानकर्ता सर्वश्री *बनाम* महादेवन और पी. वी. सुभा राव, अपीलार्थी-बैंक के प्रबंध निदेशकों को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने को 1993 के एस. एल. पी. सं.1707-08 के माध्यम से

[6] J.T. 1993 (4) S.C. 571

चुनौती दी गई थी और छुट्टी पर दिए जाने पर 1993 की सिविल अपील सं. 4017-18 का इस निर्देश के साथ निपटारा किया गया था कि उत्तरदाता के खिलाफ कोई नई जांच नहीं की जाएगी और पदोन्नति के उसके दावे पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। यह मामला अब तक उपरोक्त 1998 के एल. पी. ए. सं. 364 में निपटाया गया है। इसके और उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित कड़वी मुकदमेबाजी के दौरान अपीलकर्ता-बैंक ने उत्तरदाता को 10 मार्च, 1991 से 9 *सितंबर*, 1993 तक यानी 58 वर्ष की आयु तक सेवा में विस्तार की अनुमति दी, 9 सितंबर, 1993 के पत्र (अनुलग्नक पी-5) के माध्यम से, हालांकि मुख्य महाप्रबंधक ने उत्तरदाता को सूचित किया कि समीक्षा समिति ने भारतीय स्टेट बैंक सेवा नियमों के नियम 19 के संदर्भ में उनकी सेवा के और विस्तार की सिफारिश नहीं की थी और वह 30 सितंबर, 1998 को सेवानिवृत्त होंगे। उत्तरदाता ने एक अपील को बैंक के अध्यक्ष के समक्ष प्राथमिकता दी, अपीलीय प्राधिकरण, जिसे बर्खास्त कर दिया गया था, उन्होंने इसके बाद 1993 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 12062 दायर किया, जिसे भी 5 अक्टूबर, 1993 को एक खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था।इस आदेश को उत्तरदाता द्वारा 1993 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 17752 के माध्यम से चुनौती दी गई थी और छुट्टी दिए जाने पर 1994 की परिणामी सिविल अपील संख्या 1609 *को 11* मार्च, *1994 को डी. सी. अग्रवाल बनाम* भारतीय स्टेट बैंक और अन्य[7] को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अनुमति दी गई थीः—

> "ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग और अपीलार्थी के बीच कोई प्रेम नहीं खोया है। इससे भी अधिक इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी को उस स्थान पर काम करने के लिए तैनात किया गया था जहाँ उसके कनिष्ठ उच्च पद पर काम कर रहे थे। ए; अपपएलरथी की प्रतिक्रिया जो स्वभाव से उत्तेजक प्रतीत होती है जैसा कि वह पहले व्यक्तिगत रूप से दिखाई दिया था, उन लोगों द्वारा पारित आदेशों के लिए जो कभी उनके कनिष्ठ थे, बहुत अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती है। अपीलार्थी जो एक वरिष्ठ अधिकारी है और जिसकी आयु 58 वर्ष से अधिक है, उसे यह समझना चाहिए कि यह सेवा संस्कृति के विपरीत है। आदेशों का पालन करना और उनका पालन करना उनका कर्तव्य था। न ही उनकी ओर से अनुमति प्राप्त किए बिना छुट्टी पर जाने का कोई औचित्य था। हम यह भी देख सकते हैं कि अपीलार्थी का यह घोषणा करके कि वह बैंक का मुख्य महाप्रबंधक है, गवर्नर के साथ साक्षात्कार करने का प्रयास करना एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए अशोभनीय था। साथ ही एक कर्मचारी की सेवा के विस्तार का सामूहिक रूप से यह पता लगाने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री पर निर्णय लेना था कि क्या अपीलार्थी विस्तार का हकदार था, जब यह विवादित नहीं है कि बहुत कम अधिकारियों को अपीलार्थी की श्रेणी में 58 से 60 वर्ष तक विस्तार से इनकार कर दिया गया है। हमें इस मामले पर अपनी राय व्यक्त करने के रूप में नहीं समझा जा सकता है। लेकिन जिस बात ने हमें अपीलार्थी के विद्वान वकील से सहमत होने के लिए राजी किया है, वह यह है कि विस्तार के मामले पर प्रबंध निदेशक की एक समिति द्वारा विचार किया जाना था, जिनका पदनाम द्वारा उल्लेख किया गया है।मान लीजिए कि उनमें से कई लोग समिति के सदस्य थे। उत्तरदाता, हमारे निर्देशों के बावजूद, यह संतुष्ट करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सके कि अपीलार्थी ने उनके खिलाफ कोई आरोप लगाया था।जो भी हो, अंतिम प्राधिकारी जिसे नियमों के तहत आदेश पारित करना था, वह था कि समिति नहीं बल्कि समिति का गठन करने वाले सदस्यों की तुलना में उच्च पद पर एक अलग व्यक्ति। ऐसा प्रतीत होता है कि

[7] J.T. 1994 (2) S.C. 678

समीक्षा समिति केवल निकाय की सिफारिश कर रही है। समिति की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जाना था। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा अधिकारी हमेशा उप-प्रबंध निदेशक से उच्च पद पर होता है। दुर्भाग्य से, इस मामले में अंतिम आदेश एक ऐसे व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है जो समीक्षा समिति का सदस्य था। यह, हमारी राय में, प्रक्रिया और प्रदान की गई गाइड लाइन का घोर उल्लंघन था। यह निष्पक्षता का भी उल्लंघन है। समीक्षा आयोग केवल एक अनुशंसा करने वाला निकाय था। अंतिम आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाना था। और ऐसा होता भी नहीं दिख रहा है। हम इस बात से अवगत हैं कि अपीलीय प्राधिकरण ने अभिलेख की जांच की थी लेकिन अपीलार्थी प्राधिकरण ने इस पहलू पर अपना दिमाग नहीं लगाया जो बुनियादी और मौलिक था। इसलिए हमारी राय है कि उत्तरदाता द्वारा लिए गए निर्णय को सेवा के विस्तार द्वारा प्रदान किए गए नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके दूषित किया गया था।

परिणामस्वरूप, यह अपील सफल हो जाती है और इसकी अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय, अपीलीय प्राधिकरण और समीक्षा समिति द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे नियम में उल्लिखित कर्मियों की एक नई समिति का गठन करें। यदि अपीलार्थी ने उन उप-प्रबंध निदेशकों में से किसी के खिलाफ कोई आरोप लगाया था तो समिति में नियमों में उल्लिखित उप-प्रबंध निदेशकों के अलावा अन्य उप-प्रबंध निदेशक शामिल होंगे। पहले के उप प्रबंध निदेशक जो नई समिति के सदस्य थे। समिति की सिफारिशों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा जो समिति का गठन करने वाले सदस्यों से अलग और उच्च पद पर होंगे। ऐसी समिति का गठन आज से दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा और उसके बाद दो सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।''

(17) जैसा कि यह पाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उन कारणों से पूरी तरह से पालन नहीं किया जाएगा जो जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगे, अपीलार्थी-बैंक ने इस आदेश के स्पष्टीकरण के लिए 1994 का आई. ए. सं. 3 दाखिल किया। इसे भी 13 मई, 1994 को निम्नलिखित कार्यकालों में समाप्त कर दिया गया थाः—

''आई. ए. नं. 3/94 को बोर्ड पर लिया जाता है।

.....इस आवेदन में प्रतिवादीगण ने 11 मार्च, 1994 के आदेश में संशोधन का स्पष्टीकरण और 11 मार्च, 1994 के आदेश के अनुपालन के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अपीलकर्ता प्राधिकरण हैं और इसके परिणामस्वरूप वह अपीलार्थी के मामले पर विचार करने के लिए समिति के सदस्य के रूप में बैठकर मामले से नहीं निपट सकते हैं। यह आगे कहा गया है कि श्री एन. जी. पिल्लई और श्री आर. सिन्हा, क्रमशः उप निदेशक (कार्मिक) और उप प्रबंध निदेशक (निगमित संचालन और सेवा) के संबंध में, वे मामले को संभालने के बाद, अपीलार्थी को उनके बारे में कुछ आपत्ति है। उन परिस्थितियों में, उन्हें समिति के सदस्यों के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले निर्देश दिया गया था।

चूंकि इस न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बैंक के प्रबंध निदेशक समिति के सदस्य होंगे, इसलिए हम उत्तरदाता भारतीय स्टेट बैंक को किसी भी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंध निदेशकों में से किसी को भी अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नामित करने का निर्देश देते हैं। याचिका में उन्होंने छह व्यक्तियों के नाम दिए हैं, जिनमें से दो को समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया जा सकता है।इसके लिए याचिकाकर्ता को श्री कथुरिया, उप प्रबंध निदेशक (कोषागार और निवेश प्रबंधन) की नियुक्ति पर

कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि यह वांछनीय है *कि तीन लोगों की एक समिति मामले का फैसला करने के लिए व्यवहार्य होगी, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि श्री आर. विश्वनाथन, उप प्रबंध निदेशक (वाणिज्यिक बैंकिंग) को तीसरे सदस्य के रूप में नामित किया जाए। यह तीन सदस्यीय समिति नियमों के अनुसार 11 मार्च, 1994 के इस न्यायालय के आदेश द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में कार्यकाल बढ़ाने के लिए अपीलार्थी के दावे पर विचार करेगी* और निर्णय लेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसके बाद की किसी भी कार्यवाही में इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार समिति के विपक्ष को चुनौती देने के लिए पक्षकारों के लिए यह खुला नहीं है। समिति के गठन के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। विस्तार के दावे पर विचार करने के लिए। इसके बाद, सक्षम प्राधिकारी को निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।''

(18) माननीय उच्चतम न्यायालय के समयबद्ध निर्देशों का पालन करते हुए, 27 मई, 1994 को बैंगलोर में बैंक के कार्यकारी निकाय की एक बैठक आयोजित की गई और औपचारिक रूप से तीन सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री एस. दोरेस्वामी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अध्यक्ष सदस्य के रूप में, और सर्वश्री वी. विश्वनाथन और जी. कथुरिया, उप प्रबंध निदेशक (वाणिज्यिक बैंकिंग) और उप प्रबंध निदेशक (कोषागार और निवेश प्रबंधन), क्रमशः अन्य दो सदस्यों के रूप में करेंगे।श्री एस. दोरेस्वामी को भी सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। सर्वश्री आर. विश्वनाथन और जी. कथुरिया ने 6 और 9 जून, 1994 को आयोजित दो बैठकों के बाद 16 जून, 1994 को अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी, श्री एस. दोरेस्वामी को अनुलग्नक पी-7 में यह सिफारिश करते हुए अपनी सिफारिश की कि उत्तरदाता को 58 वर्ष से अधिक की सेवा में विस्तार देना बैंक के हित में नहीं है। इस प्रस्ताव की जांच की गई और उसी दिन सक्षम *प्राधिकारी* द्वारा स्वीकार कर लिया गया-आदेश अनुलग्नक पी-8 के माध्यम से इसके बाद समिति के तीनों सदस्यों ने मुलाकात की और 18 जून, 1994 को आयोजित कार्यवाही के कार्यवृत्त को दर्ज किया, जो अनुलेखन पी-7 और 16 जून, 1994 के आदेश अनुलेखन पी-8 में समाप्त हो गया था। आदेश अनुलग्नक पी-8 से व्यथित होकर उत्तरदाता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 1995 का नंबर 4 दायर किया जिसे वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था और समिति के निर्णय के खिलाफ अपना उपाय मांगने के लिए उसे खुला छोड़ दिया गया था। यह इस पृष्ठभूमि में है कि उत्तरदाता ने C.W.P.No दाखिल किया। 1995 का 5567 आउट।जिनमें से वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है।

(19) विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता समीक्षा समिति के गठन को चुनौती नहीं दे सकता था क्योंकि यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया कि समीक्षा समिति ने अपने रिकॉर्ड का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं किया था क्योंकि अनुलग्नक R-1 जिस पर यह आधारित था, मुख्य महाप्रबंधक द्वारा की गई सिफारिश ने उनके सेवा रिकॉर्ड की सटीक तस्वीर नहीं दी थी, और यह कि बैंक और उत्तरदाता के बीच लंबित मुकदमेबाजी ने समीक्षा समिति के सदस्यों की निष्पक्षता को कम कर दिया था। विशेष रूप से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने नोट किया कि अनुलग्नक R-1 के पैरा (डी) में की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का संदर्भ था, श्री ए. आर. रस्तोगी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में पूरी तरह से अनुचित निष्कर्ष दर्ज किया गया था कि उत्तरदाता के खिलाफ साक्ष्य को उसके आचरण को बदनाम करने के इरादे से गढ़ा गया था और इस निष्कर्ष का समर्थन न्यायालय ने 1989 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या *15874 डी.* सी. *अग्रवाल बनाम भारत* राज्य (सुप्रा) में और सर्वोच्च न्यायालय ने *भारतीय स्टेट बैंक बनाम* डी. *सी. अग्रवाल* (सुप्रा) में किया था, जिसके परिणामस्वरूप जांच अधिकारी की टिप्पणियों को उच्चतम स्तर पर न्यायिक अनुमोदन प्राप्त हुआ था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह भी कहा गया था कि बार-बार मुकदमेबाजी के संदर्भ में, जिसमें

उत्तरदाता-रिट याचिकाकर्ता अपीलार्थी-बैंक के साथ और उसके तीन ए. सी. आर(सभी एक ही अधिकारी द्वारा एक दिन में दर्ज किए गए) में शामिल था, टी. ई. जी. स्केल VII में पदोन्नति के लिए उसका साक्षात्कार किए जाने से ठीक चार दिन पहले इस निष्कर्ष का समर्थन किया कि समीक्षा समिति के समक्ष उत्तरदाता मामले को पूर्वाग्रहित करने का एक ठोस प्रयास किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस विचार के लिए कुछ समर्थन इस तथ्य से भी मांगा कि बैंक के दो अधिकारी, अर्थात् सर्वश्री इरफान सिंह और जे. के. जैन, जिनके प्रदर्शन को खराब आंका गया था और जिन्हें कई बार पदोन्नति के लिए नजरअंदाज किया गया था, उन्हें अभी भी क्रमशः 5 फरवरी, 1992 और 17 फरवरी, 1993 को 60 साल तक सेवा में विस्तार दिया गया था, जबकि कहीं बेहतर रिकॉर्ड वाले उत्तरदाता की उपेक्षा की गई थी। न्यायालय ने तदनुसार अभिनिर्धारित किया कि समीक्षा समिति और उसके बाद सक्षम प्राधिकारी की कार्रवाई मनमाना थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विपरीत होने के कारण इसे निरस्त किया जा सकता है। उपरोक्त रूप में अभिनिर्धारित करने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और अनुलग्नक पी-7 और पी-8 को रद्द कर दिया। वर्तमान अपील इस फैसले के खिलाफ दायर की गई है जबकि प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता द्वारा भी क्रॉस आपत्तियां दायर की गई हैं। अपील के साथ-साथ 1999 की एल. पी. ए. संख्या 81 के रूप में पंजीकृत प्रति-आपत्तियों/अपील का भी इस निर्णय द्वारा निपटारा किया जा रहा है।

(20) श्री अशोक अग्रवाल ने आग्रह किया है कि उनके समक्ष उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विद्वान एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष इस विषय पर तथ्यों और कानून के विपरीत था। उन्होंने इंगित किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि मुख्य महाप्रबंधक द्वारा समीक्षा समिति के विचार के लिए अपनी सिफारिश अनुलग्नक आर-1 को अग्रेषित करते समय जानबूझकर प्रयास किया गया था, वास्तव में इस कारण से गलत था कि सिफारिश अनुलग्नक आर-एल जो एक निर्धारित प्रारूप पर थी, उत्तरदाता के रिकॉर्ड के वफादार पुनरुत्पादन से संबंधित थी। वह विशेष रूप से, यह इंगित किया गया है कि विभिन्न कारक जो उत्तरदाता के पक्ष में थे, उन्हें उनके खिलाफ समान रूप से नोट किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि 1989 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 15874 में श्री ए. के. रस्तोगी और विद्वान एकल न्यायाधीश के बयानों का उच्चतम न्यायालय द्वारा समर्थन किया गया था, सही नहीं था क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को विशेष रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि सजा का आदेश दूषित था क्योंकि कुछ सामग्री जो उत्तरदाता को पूछताछ के दौरान प्रदान की जानी चाहिए थी, उन्हे प्रदान नहीं की गई थी। यह भी आग्रह किया गया है कि श्री हरभजन सिंह और श्री जे. के. जैन का सेवा रिकॉर्ड (जिसने उत्तरदाता के पक्ष में संतुलन झुकाया प्रतीत होता है) वास्तव में उत्तरदाता की तुलना में कहीं अधिक था और इस रिकॉर्ड की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है जो फाइल में है। अंत में यह दलील दी गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड *जयपुर और अन्य बनाम जगमोहन लाई*[8] में *एक समान* नियम का अर्थ लगाता है, ने कहा था कि एक अधिकारी को सेवानिवृत्ति यानी 58 वर्ष तक सेवा में रहने का अधिकार है, लेकिन उस आयु से आगे उसे ऐसा कोई अधिकार नहीं है जब तक कि बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार के तहत उसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता है और विस्तार देने या अस्वीकार करने के मामले में मनमानेपन की शिकायत करने की कोई गुंजाइश नहीं है। श्री अग्रवाल ने तदनुसार आग्रह किया है कि ऊपर उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बावजूद, और निर्णय में विस्तार से उद्धृत किए जाने के बावजूद, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उत्तरदाता को सेवा में विस्तार देने से इनकार करने वाले अपीलार्थी-बैंक की कार्रवाई मनमानेपन से दूषित थी।

[8] A.I.R. 1989 S.C. 75.

(21) हालांकि, उत्तरदाता ने कुछ निश्चित मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह आग्रह किया गया है कि उत्तरदाता मामले में अपीलकर्ता बैंक की नीति का पालन नहीं किया गया था क्योंकि संस्थान में उसके खिलाफ स्पष्ट रूप से पूर्वाग्रह और भेदभाव था। यह भी आग्रह किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने तथाकथित आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा था कि समीक्षा समिति का एक सदस्य एक सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और उस स्थिति में दोनों क्षमताओं में श्री एस. दोरेस्वामी की नियुक्ति खराब थी। इस बात पर भी बहुत जोर दिया गया है कि जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि समीक्षा समिति में तीन सदस्य होंगे, इसलिए सर्वश्री आर. विश्वनाथन और जी. कथुरिया द्वारा 16 जून, 1993 को दी गई अनुलग्नक पी-7 की सिफारिश, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत होने के कारण, कानून की दृष्टि से गलत थी। अंत में यह भी तर्क दिया गया है कि *सक्षम प्राधिकारी* यानी श्री एस. दोरेस्वामी की कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित थी और इस तरह इसे कायम नहीं रखा जा सकता था।

(22) हमने पक्षों द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हम सबसे पहले विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों के संबंध में श्री अशोक अग्रवाल द्वारा संबोधित तर्कों को संबोधित करते हैं। हम सबसे पहले मुख्य महाप्रबंधक, चंडीगढ़ मुख्य कार्यालय द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में उठाई गई आपत्तियों के प्रश्न पर विचार करते हैं। हमारी राय है कि दस्तावेज़ अनुलग्नक आर-एल को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। धनबाद में अपने कार्यकाल के दौरान कुछ दुर्व्यवहार के लिए उत्तरदाता के निलंबन का विवरण देते हुए, अनुलग्नक बी में इस तथ्य का भी स्पष्ट संदर्भ दिया गया है कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में टी. ई. जी. स्केल VI में अपने मूल कैडर में बहाल कर दिया गया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुलग्नक आर-एल एक ऐसे तथ्य से संबंधित है जो गलत था। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस तथ्य से भी बहुत प्रभावित थे कि श्री रस्तोगी द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य का निर्माण और श्री ए. के. रस्तोगी द्वारा दी गई राय कि उत्तरदाता को बैंक द्वारा पीड़ित किया गया था और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई अन्याय और पूर्वाग्रह की पूर्ववर्ती रिट याचिका में भारतीय स्टेट बैंक बनाम डी. सी. अग्रवाल (सुप्रा) के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले का निपटारा करते हुए *सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समर्थन* किया *गया था। यह* विचार इस कारण से भी पूरी तरह से सही नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि अपील में कई मुद्दे उठाए गए थे, फिर भी इसका निपटारा इस सीमित आधार पर किया जा रहा था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट की गैर-आपूर्ति, जिस पर दंडक प्राधिकरण द्वारा भरोसा किया गया था, उत्तरदाता को प्रदान नहीं की गई थी, जिससे जांच के दौरान उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ।

(23) विद्वान एकल न्यायाधीश ने कुछ हद तक उत्तरदाता के तुलनात्मक सेवा रिकॉर्ड पर भी भरोसा किया है, जबकि *सर्वश्री* हरमन सिंह और जे. के. जैन को 60 साल तक का विस्तार दिया गया था और एक निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि इन दोनों अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड खराब था, जबकि उत्तरदाता का रिकॉर्ड कहीं बेहतर था। हमने दलीलों का अध्ययन किया है और पाया है कि रिट याचिका में सर्वश्री हरमन सिंह और जे. के. जैन के सेवा रिकॉर्ड के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन जवाब के प्रत्युत्तर में पृष्ठ 6 पर एक तुलनात्मक चार्ट दिया गया है, और दलीलों के दौरान उत्तरदाता ने इन दोनों अधिकारियों के कथित रूप से खराब रिकॉर्ड को दर्शाने वाला एक और चार्ट प्रस्तुत किया है। जब अपनी जानकारी के स्रोत का खुलासा करने के लिए कहा गया, तो उत्तरदाता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि यह चार्ट उसके द्वारा रिकॉर्ड के निरीक्षण पर तैयार किया गया था, जबकि यह विद्वान एकल न्यायाधीश के न्यायालय में था। और यह कि उनके द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया मूल्यांकन उनके अपने शब्दों में था। हमारी राय है कि उत्तरदाता द्वारा दिए गए विवरणों की कोई पवित्रता नहीं है क्योंकि केवल प्रतिकूल विशेषताओं को चुनिंदा रूप से उठाया गया है और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश के

इस निष्कर्ष के लिए एक सटीक आधार नहीं हो सकता है। यद्यपि यह न्यायालय अन्य दो अधिकारियों की तुलना में उत्तरदाता के सेवा रिकॉर्ड का तुलनात्मक मूल्यांकन करने में समीक्षा समिति की कार्रवाई पर एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप *में* कार्य नहीं कर सकता है, फिर भी हमने इस अभ्यास को करने के लिए चुना है ताकि उन कारणों को पूरा किया जा सके जो रिट कोर्ट के साथ वजन करते हैं।वर्तमान अपील में 1998 की सी. एम. संख्या 1147 के साथ दायर किए गए अनुलग्नक ए-एल और ए-2 के रूप में दोनों अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड हमारे सामने है। यह अभिलेख 60 वर्ष तक सेवा के विस्तार की मंजूरी देने वाली कार्यवाही से संबंधित है जिसमें विस्तार की तारीख से पहले के तीन वर्ष के अभिलेख को ध्यान में रखा जाना है। दस्तावेज़ अनुलग्नक ए-एल में श्री जे. के. जैन के समग्र प्रदर्शन को कुछ मापदंडों में उत्कृष्ट श्रेणीकरण के साथ अच्छा आंका गया है। नियंत्रक प्राधिकरण ने तदनुसार सुझाव दिया कि उसे 60 वर्ष तक का विस्तार दिया जाए। समान रूप से, हमने श्री हरभजन सिंह से संबंधित अनुलग्नक ए-2 का अध्ययन किया है।जिस मामले में पिछले तीन वर्षों के एसीआर को भी जोड़ा गया है और हम पाते हैं कि समग्र मूल्यांकन कम से कम अच्छा है। हमारे लिए यह स्पष्ट है कि प्रत्येक अधिकारी को पदोन्नति या सेवा में विस्तार के लिए अपने मामले पर निष्पक्ष विचार करने का अधिकार है और यदि यह अभ्यास निष्पक्ष रूप से किया जाता है, तो कोई भी अधिकारी मनमानेपन की शिकायत नहीं कर सकता है। हमारी राय है कि वर्तमान मामले में यह अभ्यास निष्पक्ष रूप से किया गया है।

(24) उत्तरदाता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि 60 वर्ष तक सेवा में विस्तार के अनुदान या इनकार के लिए परिकल्पित प्रक्रिया का समीक्षा समिति द्वारा पालन नहीं किया गया था और इस अतिरिक्त कारण से आक्षेपित आदेश कानून में खराब थे। यह रेखांकित किया गया है कि विस्तार अनुलग्नक पी-2 के अनुदान के लिए नीति के अनुसार बैंक किसी भी प्रतिकूल आदेश को पारित करने से पहले उत्तरदाता के ध्यान में एक खराब या औसत रिकॉर्ड लाने के लिए बाध्य था और क्योंकि ऐसा नहीं किया गया था, यह धारणा थी कि उसका रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा था। यह आग्रह किया गया है कि हालांकि इनकार करना या विस्तार देना बैंक का विवेकाधिकार था, लेकिन उपरोक्त कारक के कारण उसके खिलाफ विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। हालांकि, श्री अशोक अग्रवाल ने उत्तरदाता के दावे का खंडन किया है और कहा है कि यह बैंक को अपने विवेक पर उत्तरदाता को 60 साल तक सेवा में बनाए रखने की उपयुक्तता पर निर्णय लेना था और एकमात्र विचार यह था कि क्या उत्तरदाताओ को जारी रखा जाए। यह उसके हित में था या नहीं। इस संबंध में श्री अग्रवाल ने भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षी कर्मचारी) सेवा नियम 1975 के नियम 20 (जिसे बाद में "1975 का नियम" कहा गया है) और भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी सेवा नियम, 1992 के नियम 19 (जिसे बाद में "सेवा नियम" कहा गया है) के साथ-साथ याचिकाकर्ता को दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4 और 6, अनुलग्नक पी-2 पर भरोसा जताया है। सेवा नियमों के 1975 और 19 के नियमों के नियम 2 में यह प्रावधान है कि बैंक का एक अधिकारी 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा, हालांकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा में विस्तार अपने विवेक से 58 वर्ष से अधिक दिया जा सकता है यदि वह पाता है कि बैंक के हित में विस्तार वांछनीय है। गाइड लाइन के पैराग्राफ 4 और 6 में सेवा में विस्तार या इसके इनकार के लिए मानदंड दिए गए हैं और अन्य बातों के साथ-साथ यह *अभिनिर्धारित किया* गया है कि एक अधिकारी जो अच्छा प्रदर्शन करता है, कुशल है और अच्छा स्वास्थ्य रखता है, उसे सेवा में विस्तार के अनुदान के लिए उपयुक्त माना जाना चाहिए और इसके विपरीत, एक अधिकारी जिसका प्रदर्शन खराब है या जिसकी ईमानदारी संदेह से परे नहीं है या जो अक्षम है या खराब स्वास्थ्य में है, उसे सेवा में विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। यह भी निर्धारित किया गया है कि विस्तार के अनुदान के लिए उपयुक्त अधिकारी पर विचार करने के लिए मार्गदर्शक कारक बैंक के लिए उसकी उपयोगिता और उपयोगिता थी। गाइड-लाइन के पैराग्राफ 6 में आगे कहा गया है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों से उत्पन्न अधिकारी के प्रदर्शन से

संबंधित विवरण नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में दाखिल किए जाने चाहिए जिन्हें समीक्षा समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जाना चाहिए। जगमोहन लाई के मामले (उपरोक्त) में एक समान स्थिति से निपटने के दौरान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः—

> "यहाँ दी गई योजना में उत्तरदाता या बैंक के किसी अन्य अधिकारी को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने का वैध अधिकार है।लेकिन उस उम्र के बाद, उसे ऐसा कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उसकी सेवा बैंक द्वारा नहीं बढ़ाई जाती है।पक्षों के आगे के अधिकारों को विनियमन के प्रावधान द्वारा विनियमित किया जाता है प्रावधान19(1) इसमें लिखा हैः—
>
> बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार पर ऐसे अधिकारी की सेवा की अवधि बढ़ा सकता है जिसकी आयु अड़तालीस वर्ष हो गई है या जिसने तीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, यदि ऐसा विस्तार बैंक के हित में वांछनीय समझा जाता है।
>
> इसलिए सेवा विस्तार देने का एकमात्र उद्देश्य बैंक के हित को बढ़ावा देना है न कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को कोई लाभ प्रदान करना। संयोग से, इस विस्तार से सेवानिवृत्त अधिकारियों को लाभ हो सकता है। लेकिन यह अधिकारियों को विशेषाधिकार का लाभ प्रदान करना है। यदि बैंक यह समझता है कि किसी अधिकारी की सेवा बैंक के हित में वांछनीय है, तो यह उसे सेवानिवृत्ति की आयु से परे सेवा में बने रहने की अनुमति दे सकता है। यदि बैंक यह मानता है कि सेवानिवृत्ति के बाद किसी अधिकारी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, तो यह मामला समाप्त हो जाता है। यह अधिकारी पर कोई प्रतिबिंब नहीं है। इसमें कोई कलंक नहीं है..
>
> हालांकि, बैंक को (i) निरंतर उपयोगिता (ii) अच्छा स्वास्थ्य और (iii) अधिकारी की निंदा से परे ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत अधिकारियों के मामले पर विचार करना आवश्यक है। यदि अधिकारी के पास एक या दूसरे की कमी है, तो बैंक उसे सेवा का विस्तार देने के लिए बाध्य नहीं है। इस मामले में, बैंक ने उच्च न्यायालय को दिखाया है कि उत्तरदाता के मामले पर विचार किया गया था और वह उक्त दिशानिर्देशों में फिट नहीं था। उच्च न्यायालय उस फैसले के खिलाफ अपील में नहीं बैठता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय उस निर्णय की समीक्षा नहीं कर सकता है।
>
> बैंक के पास सभी अधिकारियों की सेवाओं का विस्तार करने का कोई दायित्व नहीं है, भले ही वे हर मामले में उपयुक्त पाए जाएं। सेवा का विस्तार देने के लिए बैंक का ब्याज प्राथमिक विचार है। सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बैंक एक वर्ष में सभी उपयुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों को कार्यकाल विस्तार दे सकता है। एक अन्य वर्ष में, यह कुछ को विस्तार दे सकता है और सभी को नहीं, बाद के वर्ष में, यह किसी भी अधिकारी को विस्तार नहीं दे सकता है। बैंक में एक वर्ष में बहुत सारी नई भर्तियां हो सकती हैं। हो सकता है कि बैंक को किसी अन्य वर्ष में सभी सेवानिवृत्त व्यक्तियों की सेवाओं की आवश्यकता न हो।आने वाले वर्ष में बैंक पर काम का बोझ कम हो सकता है। सेवानिवृत्त व्यक्ति किसी भी वर्ष में "सभी या किसी के लिए विस्तार" की मांग नहीं कर सकते हैं। यदि हम सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के उस अधिकार को स्वीकार करते हैं, तो बैंक के बीच में विस्तार देने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसलिए, हमारी राय है कि सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को सेवा का विस्तार देने के मामले में मनमानेपन की शिकायत करने की कोई गुंजाइश नहीं है।"

(25) विद्वान एकल न्यायाधीश ने समीक्षा समिति की सिफारिशों को इस कारण से मनमाना पाया है कि नियंत्रक प्राधिकरण यानी मुख्य महाप्रबंधक, चंडीगढ़ ने अपनी सिफारिश को अग्रेषित करते हुए अनुलग्नक R-1 ने प्रतिवादीगण के रिकॉर्ड की गलत तस्वीर पेश की थी। हम उन कारणों के लिए राय रखते हैं, जो पहले से ही दर्ज हैं, कि अनुलेखन R-1 की सिफारिश उनके सेवा जीवन का एक वफादार पुनरुत्पादन था और चूंकि प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर आगे बढ़ाया गया था, इसलिए नियंत्रण प्राधिकारी को कुछ मामलों को विचार से बाहर रखने का कोई विवेकाधिकार नहीं था।

(26) उत्तरदाता ने समीक्षा समिति के गठन और शक्ति को भी गंभीर चुनौती दी है। सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि डी. सी. अग्रवाल बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य[9] मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक *में, जैसा कि* आदेश *द्वारा स्पष्ट किया गया है, 1994 की* आई. ए. संख्या 3 पर बनाई गई तारीख 13 मई, 1994, यह अनिवार्य था कि -समीक्षा समिति में तीन सदस्य होते हैं और एक अन्य उच्च पद का व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी होता है और चूंकि उनके मामले पर सर्वश्री जी. कथुरिया और आर. विश्वनाथन की दो सदस्यीय समिति द्वारा विचार किया गया है, इसलिए की गई सिफारिशों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है और इसलिए यह कानूनन गलत है। हालाँकि, श्री अहोक अग्रवाल ने इस रुख का विरोध किया है और आग्रह किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण आदेश में विशेष रूप से निर्देश दिया गया था कि समीक्षा समिति नियमों के अनुसार मामले का निर्णय करेगी और नियमों द्वारा दो की कोरम प्रदान की गई थी, नियमों के अनुसार लिया गया निर्णय पूरी तरह से क्रम में था। इस संबंध में, दोनों पक्षों द्वारा 4 जनवरी, 1998 के अनुलग्नक पी-2 पर निर्भरता रखी गई है। इन मार्गदर्शक पंक्तियों की व्याख्या प्रतिवादीगण के मामले में इस पैराग्राफ में ऊपर सूचीबद्ध दो मामलों में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के आलोक में की जानी चाहिए और जिन्हें वर्तमान अपील में निर्णय के पहले भाग में विस्तार से पुनः प्रस्तुत किया गया है (इस निर्णय के पृष्ठ 3441) यह सच है कि इस तथ्य के लिए बार-बार संकेत हैं कि तीन सदस्यीय समिति को प्रतिवादीगण के दावे पर विचार करना और निर्णय लेना वांछनीय और व्यवहार्य होगा, लेकिन 13 मई, 1994 के आदेश में यह निर्देश दिया गया है कि विस्तार के लिए उनके दावे पर भी नियमों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। विचाराधीन नियम 1975 के नियम, सेवा नियम और निर्देश अनुलग्नक पी-2 हैं, जिसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा समिति द्वारा की जानी चाहिए। विशेष रूप से उस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक जिसमें समिति के कम से कम दो सदस्य उपस्थित हों। मान लीजिए, समीक्षा समिति के दो सदस्यों ने अनुलग्नक पी-7 की सिफारिश की थी। उत्तरदाता ने इस तथ्य पर भी बहुत जोर दिया है कि श्री एस. दोरेस्वामी, जो सक्षम प्राधिकारी थे, इस तरह से कार्य नहीं कर सकते थे कि उन्हें समीक्षा समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था न कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में। यह तर्क इस कारण से भी अस्वीकार्य है कि सर्वोच्च न्यायालय उस स्थिति से अच्छी तरह से अवगत था जिसमें पक्षकार उस समय खड़े थे जब उन्होंने दोनों आदेश दिए थे। यह ध्यान में रखना होगा कि न्यायालय ने विशेष रूप से यह प्रावधान किया था कि सक्षम प्राधिकारी समीक्षा समिति का गठन करने वाले सदस्यों की तुलना में उच्च पद का व्यक्ति होगा और इस कारण से अपीलकर्ता-बैंक के लिए किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंध निदेशक को समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नामित करने के लिए खुला छोड़ दिया था। श्री जी. कथुरिया, जो उत्तरदाता को स्वीकार्य थे, और श्री आर. विश्वनाथन, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित किया गया था, स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक थे, जबकि श्री एस. दोरेस्वामी, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक की कार्यकारी समिति द्वारा 27 मई, 1994 के अपने

[9] 1994 Supp. (2) S.C.C. 131

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया था, भारतीय सेंट्रल बैंक के प्रबंध निदेशक सह-अध्यक्ष थे और इस प्रकार समीक्षा समिति के सदस्यों से उच्च पद पर थे।यह भी सच है कि अनुलग्नक पी-2 में यह प्रावधान किया गया है कि टी. ई. जी. स्केल VI और उससे ऊपर के अधिकारियों के मामले में पुनरीक्षण समिति में प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक (कार्मिक और प्रबंधन) और उप प्रबंध निदेशक (कॉर्पोरेट, संचालन और सेवा) को पदनाम द्वारा शामिल किया जाना था, जबकि सक्षम प्राधिकारी को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक होना था, लेकिन हमारी राय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप समीक्षा समिति और गाइड-लाइन अनुलग्नक पी-2 के तहत परिकल्पित सक्षम प्राधिकारी को प्रतिस्थापित किया गया था, इस तथ्य के कारण कि प्रतिवादीगण के मामले से निपटने के लिए एक उचित व्यवस्था के रूप में कि मुकदमेबाजी का एक लंबा और कड़वा इतिहास था, जो लगभग दो दशकों से फैला हुआ था और वहां था। प्रतिवादीगण के मामले पर नियमों के अनुसार अन्यथा विचार किया जाना था, जिसमें श्री एस. दोरेस्वामी ने सक्षम प्राधिकारी की जगह ली और सर्वश्री कथुरिया और आर. विश्वनाथन ने समीक्षा समिति के सदस्यों के रूप में दो अन्य नामित उप प्रबंध निदेशकों की जगह ली। ऊपर वर्णित सभी बातों के आलोक में, हमारी राय है कि आदेशों को जब एक साथ पढ़ा जाता है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि उत्तरदाता ने भी इस स्थिति को इस कारण से स्वीकार किया है कि उसने अपनी दलीलों के दौरान और यहां तक कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष भी दो सदस्यीय समीक्षा समिति और सक्षम प्राधिकारी के गठन पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी और यह इस अपील में हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्नों के कारण था जिसने उसे पहली बार इस याचिका को लेने के लिए प्रेरित किया।

(27) उत्तरदाता ने सक्षम प्राधिकारी और समीक्षा समिति के सदस्यों की नियुक्ति को चुनौती देते हुए एक याचिका भी दायर की है। उन्होंने, विशेष रूप से, श्री एस. दोरेस्वामी की नियुक्ति पर इस दलील पर गंभीर आपत्ति जताई है कि वे भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष की सेंट्रल बैंक के प्रबंध निदेशक-सह-अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए बहुत ऋणी थे। हम इस याचिका को पूरी तरह से असमर्थनीय पाते हैं क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 के आई. ए. संख्या 4 में 13 मई, 1994 के अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि पक्षकार स्वयं न्यायालय के आदेशों के तहत गठित समीक्षा समिति के गठन को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे।

(28) इसलिए, हमारी राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है। यह अपील तदनुसार सफल होती है, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप रिट याचिका खारिज हो जाती है। *वस्तुतः L.P.A. No. 81 of 1999* के रूप में पंजीकृत प्रति-आपत्ति को भी खारिज कर दिया जाता है।

(29) इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान, दोनों पक्षों ने अदालत में बड़ी संख्या में दस्तावेज दायर किए हैं। न्याय के हित में, हमने कानूनी प्रक्रिया से बंधे बिना सब कुछ रिकॉर्ड में ले लिया है।

(30) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 16 नवंबर, 1998 के अपने आदेश में निर्देश दिया था कि अपीलों का किसी भी स्थिति में 1 मार्च, 1999 तक निपटारा किया जाए। इस समय अनुसूची का पालन मुख्य रूप से इस कारण से नहीं किया जा सका कि उत्तरदाता ने सर्वोच्च न्यायालय से कुछ निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा था जो इस न्यायालय द्वारा 13 जनवरी, 1999,1 फरवरी, 1999 और 2 फरवरी, 1999 को दिए गए आदेशों से स्पष्ट होगा। अपीलों पर अंततः 15 फरवरी, 1999 को दिन-प्रतिदिन की सुनवाई के लिए विचार किया गया और दलीलें पूरी की गईं और 24 फरवरी, 1999 को फैसला सुरक्षित रखा गया।

(31) उपर्युक्त अपीलों का तदनुसार निपटान किया जाता है, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

आर. एन. आर.

न्यायमूर्ति जवाहर लाई गुप्ता और न्यायमूर्ति एन. सी. खिची के समक्ष

वी. के. खन्ना,-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य,-उत्तरदाता

1998 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 8150

21 दिसंबर, 1998

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-किसी *जांच को रोकने या आरोप पत्र को रद्द करने के लिए याचिका-ऐसी रिट याचिका को बनाए रखने कि क्षमता।*

अभिनिर्धारित किया कि एक रिट अदालत आम तौर पर किसी जांच को रोकने या आरोप पत्र को रद्द करने के लिए हस्तक्षेप नहीं करती है। हालाँकि, वर्तमान मामले में हम संतुष्ट हैं कि मौन सही विकल्प नहीं होगा। जब चीजें गलत तरीके से की जाती हैं, तो मौन एक पाप है। वर्तमान मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है जहां अदालत को अन्याय को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए।

(पैरा 103)

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-एक आई. ए. एस. अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र-याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच-याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं किए गए दस्तावेजों का दावा-चाहे उचित अवसर से इनकार किया गया हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य सरकार के पास नियमों के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की शक्ति है।

(पैरा 103)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता को उचित अवसर देने से इनकार किया गया था क्योंकि उसे दस्तावेजों की प्रतियां या अभिलेख का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई थी। यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी।प्रतिवादीगण ने न्यायपूर्ण और निष्पक्ष जांच के लिए बुनियादी नियमों और मानदंडों का पालन नहीं किया है। उन्होंने न्यूनतम गारंटी का उल्लंघन किया है कि अधिकारी को एक प्रभावी अधिकार दिया जाएगा।

(अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।)

रवि अमितोज़, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी